राजस्थान समसामयिकी फरवरी, 2025

संजीव वेबसाइट से नि:शुल्क डाउनलोड करें
राजस्थान की आर्थिक समीक्षा एवं बजट का सार संग्रह;
राजस्थान, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय समसामयिकी (प्रत्येक माह)
साथ ही संजीव वेबसाइट से आप E-Book भी खरीद सकते हैं।
visit us at : www.sanjivprakashan.com

राजस्थान समसामयिकी फरवरी, 2025
(Current News from Daily Newspapers)

Newspaper of 1 February, 2025

■ **राज्यपाल ने सोलहवीं राजस्थान विधानसभा में अभिभाषण दिया–**

31 जनवरी, 2025 को राजस्थान के राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने सोलहवीं राजस्थान विधानसभा के तृतीय सत्र में अभिभाषण दिया।

- विधानसभा के मुख्य द्वार पर राज्यपाल श्री बागड़े को आरएसी बटालियन द्वारा सलामी दी गई।
- राज्यपाल ने विधानसभा में एक घंटे 27 मिनट में अपना अभिभाषण पूरा किया।

  राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर तक ले जाना हमारा लक्ष्य है।
- इसे साकार करने के उद्देश्य से 'राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट' सरकार की दूरदर्शी सोच का सफल उदाहरण है।
- कार्यकाल के पहले ही साल में समिट का आयोजन कर 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश की मजबूत बुनियाद रखी गई है।

■ **राम जल सेतु लिंक परियोजना; 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी**

राज्यपाल बागड़े ने विधानसभा में कहा कि राजस्थान सरकार, मध्यप्रदेश के साथ मिलकर इस परियोजना के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए संकल्पित है और 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर परियोजना का कार्य शुरू किया गया है।

- कोटा में कालीसिन्ध नदी पर नवनेरा बांध का निर्माण अक्टूबर, 2024 में पूरा कर लिया गया है।
- भारत सरकार, हरियाणा तथा राजस्थान के मध्य हुए समझौते के आधार पर यमुना का जल लाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।

Newspaper of 3 February, 2025

■ **दिसंबर 2024 में जयपुर देश का 11वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट रहा; वर्ष 2024 में 58.73 लाख यात्रियों ने–**

दिसम्बर, 2024 में जयपुर एयरपोर्ट यात्रीभार के लिहाज से देश का 11वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट रहा

वर्ष 2024 में जयपुर एयरपोर्ट देश का 13वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट रहा है। वर्ष 2024 में जयपुर एयरपोर्ट से 58.73 लाख अधिक यात्रियों ने यात्रा की है। यह पिछले साल की तुलना में 9 फीसदी से अधिक है। वर्ष 2023 में जयपुर एयरपोर्ट से 53.86 लाख यात्रियों ने यात्रा की थी।

जयपुर एयरपोर्ट ने यात्रीभार के लिहाज से गुवाहाटी और लखनऊ एयरपोर्ट को पीछे छोड़ दिया है। दिसंबर, 2024 में जयपुर एयरपोर्ट से 5.90 लाख यात्रियों ने यात्रा की है। जबकि गुवाहाटी एयरपोर्ट पर 5.83 लाख और लखनऊ एयरपोर्ट पर 5.85 लाख यात्रियों की संख्या रही है।

प्रमुख एयरपोर्ट एवं उनका यात्रीभार वर्ष, 2024

एयरपोर्ट	यात्रीभार
दिल्ली	7.78 करोड़
मुंबई	5.48 करोड़
बेंगलुरु	4.07 करोड़
हैदराबाद	2.78 करोड़
चेन्नई	2.19 करोड़
कोलकाता	2.12 करोड़
अहमदाबाद	1.27 करोड़
कोच्चि	1.09 करोड़
पुणे	1.02 करोड़
गोवा दाबोलिम	70.43 लाख
लखनऊ	63.21 लाख
गुवाहाटी	59.55 लाख
जयपुर	58.73 लाख

Newspaper of 5 February, 2025

■ **राजस्थान कैबिनेट की बैठक में महत्त्वपूर्ण निर्णए लिए गए–**

- विश्वविद्यालयों में कुलपति के पदनाम में परिवर्तन कर 'कुलगुरु' किया गया। प्रति कुलपति का पदनाम प्रति कुलगुरु किया है।
- राज्य के 2 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार की सही राह दिखाने के लिए पंचायत स्तर पर काउंसलिंग सेंटर खोले जाएंगे।
- राजस्थान कर बोर्ड का राजस्व मंडल में विलय किया जाएगा।
- विधानसभा सचिवालय में मुख्य सम्पादक का पद सृजित।

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

■ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 'मेरी पॉलिसी मेरे हाथ' अभियान शुरू–

4 फरवरी, 2025 को कृषि एवं उद्यानिकी सचिव राजन विशाल ने पंत कृषि भवन में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पॉलिसियों का वितरण कर रबी 2024-25 की 'मेरी पॉलिसी मेरे हाथ' अभियान के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

- कृषकों को समय पर बीमा पॉलिसी की हार्ड कॉपी नहीं मिलने से खराब होने पर फसल की जानकारी एवं किसानों को बीमा के प्रति जागरुक करने के लिए पूरे प्रदेश में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शिविर लगाकर पॉलिसियों का वितरण 15 मार्च तक किया जाएगा।
- 05 फरवरी से आयोजित किये जा रहे एग्रोस्टेक योजना के कैम्पों में भी कृषि पर्यवेक्षकों द्वारा पॉलिसियों का वितरण किया जाएगा।
- जो किसान इन शिविरों में पॉलिसी प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, वे अपनी फसल बीमा पॉलिसी संबंधित कृषि पर्यवेक्षक से प्राप्त कर सकते हैं।
- कृषकों को खरीफ फसल के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और वाणिज्यिक व बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम अदा करना पड़ता है।
- फसल बीमा सभी श्रेणी के कृषकों के लिए खरीफ 2022 से स्वैच्छिक है, लेकिन ऋणी कृषकों को योजना से पृथक होने के लिए योजना से जुड़ने की अन्तिम तिथि से सात दिन पूर्व लिखित में आवेदन किया जाना आवश्यक है।

Newspaper of 6 February, 2025

■ राजस्थान में औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के लिए 3 नई नीतियों का अनुमोदन किया गया–

प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए टैक्सटाइल एण्ड अपैरल पॉलिसी–

राज्य सरकार वस्त्र व परिधान के क्षेत्र में प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करना चाहती है।

- इसे ध्यान में रखते हुए राजस्थान टैक्सटाइल एण्ड अपैरल पॉलिसी-2025 को मंजूरी दी गई है।
- यह प्रदेश में टैक्सटाइल एण्ड अपैरल क्षेत्र के सतत् व समग्र विकास के साथ-साथ इस क्षेत्र में रोजगार सृजन, कौशल विकास, नवाचार, उत्पादकता और निर्यात को बढ़ावा देगी।
- वहीं, दूसरी ओर इससे वैश्विक स्तर पर स्थानीय वस्त्र उत्पादकों की दक्षता और विश्वसनीयता में भी वृद्धि होगी।
- इस नीति से प्रदेश के वस्त्र उत्पादक लाभान्वित होंगे और राज्य में लगभग 40 हजार करोड़ रुपये के संभावित निवेश से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

डेटा सेंटर पॉलिसी से विकसित होगा विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम–

सूचना प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर्स की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी-2025 को मंजूरी प्रदान की गई।

- इस पॉलिसी का उद्देश्य राज्य में एक विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम विकसित करना है एवं राजस्थान को डेटा सेंटर क्षेत्र में प्रमुख गंतव्य बनाना है।
- यह नीति राज्य में स्थापित होने वाले डेटा सेंटर्स की गतिविधियों की दक्षता, सुरक्षा और विश्वसनीयता को प्रभावी बनाएगी।
- इस नीति में डेटा सेंटर सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए एसेट क्रिएशन इंसेंटिव, सनराइज इंसेंटिव, ब्याज अनुदान, बैंकिंग, ट्रांसमिशन व व्हीलिंग शुल्क में छूट, भूमि संबंधी फ्लेक्सिबल भुगतान सुविधा, स्टांप ड्यूटी, भू-रूपांतरण व विद्युत शुल्क में छूट तथा बाह्य विकास शुल्क से छूट सहित कई प्रावधान किए गए हैं।
- इस नीति के क्रियान्वयन से राज्य में आगामी पाँच वर्षों में लगभग 20 हजार करोड़ रुपए का निवेश आना संभावित है।

निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी–

राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने और कनेक्टिविटी में वृद्धि करते हुए लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाने के उद्देश्य से राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2005 का अनुमोदन किया गया।

- यह नीति लॉजिस्टिक्स सुविधाओं की मैपिंग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित कर रोजगार सृजन में सहायक सिद्ध होगी।
- राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 के तहत वेयरहाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज, इनलैण्ड कन्टेनर डिपो, कन्टेनर फ्रेट स्टेशन, एयर फ्रेट स्टेशन, कार्गो टर्मिनल, ट्रकर पार्क, निजी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क और एकीकृत लॉजिस्टिक्स पार्क डेवलपर्स के लिए कैपिटल सब्सिडी, ब्याज अनुदान सहित कर एवं शुल्कों में विभिन्न रियायतों के आकर्षक प्रावधान किए गए हैं।
- रीको के आगामी औद्योगिक क्षेत्रों में अधिकतम 10 एकड़ अथवा 10% आवंटन योग्य भूमि लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के लिए आरक्षित की जाएगी।

■ राजस्थान कर बोर्ड का राजस्व मण्डल में विलय–

वर्ष 2017 से जीएसटी व्यवस्था लागू हो जाने के बाद राजस्थान कर बोर्ड का कार्य सीमित हो गया था। इसे देखते हुए राजस्थान कर बोर्ड का राजस्थान राजस्व मण्डल में विलय करने का निर्णय किया गया है।

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

■ **उभरती युवा प्रतिभाओं के प्रोत्साहन के लिए नई युवा नीति का अनुमोदन किया गया–**

राज्य मंत्रिमंडल द्वारा राजस्थान युवा नीति–2025 का अनुमोदन किया गया है। इसके जरिये गुणवत्तायुक्त शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्यमिता और बुनियादी अधिकारों तक युवाओं की पहुँच सुनिश्चित की जाएगी। यह नीति युवा नीति–2013 का स्थान लेगी। नई युवा नीति सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगी। इस नीति के माध्यम से कला, खेल, संस्कृति और साहित्य जैसे क्षेत्रों में उभरती हुई प्रतिभाओं को समर्थन भी दिया जाएगा।

■ **द राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (अमेण्डमेंट वैलिडेशन) बिल–2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया–**

रीको को हस्तान्तरित औद्योगिक क्षेत्रों के भू–रूपान्तरण एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए दि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (अमेण्डमेंट वैलिडेशन) बिल–2025 लाया जाएगा।

- इसके प्रारूप का मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदन किया गया। इस विधेयक में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 281 (2) में संशोधन द्वारा राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्तियाँ प्रत्यायोजित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।
- इसके अनुसरण में रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में अभी तक की गई भू–उपयोग परिवर्तन, उप–विभाजन लीजडीड निष्पादन, लीजहोल्ड अधिकारों का हस्तांतरण आदि कार्यवाहियों को विनियमित करने तथा भविष्य के कार्यों के लिए भी रीको को पृथक से नियम अधिसूचित करने के लिए अधिकृत किया जाएगा।
- उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा रीको को हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यमियों को आ रही परेशानियों का निराकरण इस विधेयक के पारित होने के बाद संभव हो सकेगा।

Newspaper of 9 February, 2025

■ **राजस्थान सरकार ने अंशकालीन पुजारियों का मानदेय 5 हजार रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह किया–**

8 फरवरी, 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में देवस्थान विभाग से जुड़े कई महत्त्वपूर्ण निर्णय किए गए।

- मंत्रिपरिषद् की बैठक में देवस्थान विभाग के प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी के 390 मंदिरों एवं आत्म निर्भर श्रेणी के 203 मंदिरों में सेवा पूजा, भोग, प्रसाद, उत्सव, पोशाक, जल एवं प्रकाश, सुरक्षा संचालन व्यवस्था आदि के लिए सहायता राशि को दोगुना करते हुए 3 हजार रुपये प्रति मंदिर प्रति माह किए जाने का निर्णय लिया गया।
- एक और महत्त्वपूर्ण फैसला करते हुए देवस्थान विभाग में प्रत्यक्ष प्रभार एवं आत्म निर्भर मंदिरों में कार्यरत अंशकालीन पुजारियों को दिए जा रहे मानदेय को 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रतिमाह करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
- देवस्थान विभाग के प्रबंधित एवं नियंत्रित राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार के 6 मंदिरों तथा आत्मनिर्भर श्रेणी के 26 मंदिरों के जीर्णोद्धार, मरम्मत एवं विकास कार्यों के लिये 101 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
- राज्य के बाहर स्थित देवस्थान विभाग के मंदिरों का सर्वे करवाते हुए इनकी वास्तविक संख्या पता कर इन्हें सूचीबद्ध किया जाएगा।
- जीण–शीर्ण हो चुके मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए 25 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इन निर्णयों की स्वीकृति भी मंत्रिपरिषद् की बैठक में प्रदान की गई।

Newspaper of 12 February, 2025

■ **पंचायतीराज विभाग की ओर से नई गाइडलाइन जारी हुई; 3 हजार की आबादी वाली ग्राम पंचायतों में 7, एक लाख तक की पंचायत समिति में 15 वार्ड होंगे–**

ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के नवसृजित, पुनर्सीमांकन और पुनर्गठन की प्रक्रिया अब पंचायतीराज विभाग की ओर से जारी नई गाइडलाइन के अनुसार होगी। विभाग ने वार्डों की संख्या निर्धारित करने के जो मापदण्ड तय किए हैं उसके अनुसार 3 हजार तक की आबादी वाली ग्राम पंचायतों में 7 वार्ड होंगे। तीन हजार से ज्यादा जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों में 3 हजार से अधिक प्रत्येक 1 हजार या उसके भाग के लिए 7 की संख्या में 2 वार्डों की बढ़ोतरी हो सकेगी।

पंचायत समितियों के पुनर्गठन में भी एक लाख तक की आबादी वाली पंचायत समितियों में 15 वार्ड और एक लाख से अधिक आबादी वाली पंचायत समिति में प्रत्येक 15 हजार या उसके भाग के लिए 15 वार्ड की संख्या में 2 वार्डों की बढ़ोतरी किया जाना निर्धारित किया गया है।

■ **'इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022' के तहत राज्य सरकार प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ की सब्सिडी देगी–**

राज्य सरकार ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति–2022 के तहत 200 करोड़ रुपए का ई–व्हीकल प्रमोशन फंड गठित किया गया है। राज्य सरकार की 'इलेक्ट्रिक वाहन नीति–2022' के तहत आधुनिक बैटरी युक्त इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रेताओं को स्टेट जीएसटी राशि का पुनर्भरण और एकमुश्त अनुदान ई–व्हीकल प्रमोशन

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

फंड में से दिए जाने का प्रावधान किया गया है। पुनर्भरण और एकमुश्त अनुदान राशि एक सितंबर से क्रय किए गए और राज्य में पंजीकृत किए गए वाहनों पर देय होगी। वाहन का क्रय राजस्थान राज्य से ही किया जाना आवश्यक है। अनुदान के लिए पॉलिसी के तहत फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (फेम-2) में पंजीकृत वाहन विनिर्माता को विभागीय पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के बाद विभाग की ओर से सत्यापन किए जाने के बाद निर्माता की ओर से पुन: पोर्टल पर फेम-2 के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आधुनिक बैटरी युक्त वाहन का मॉडल, बैटरी का प्रकार व बैटरी क्षमता की सूचना दर्ज की जाएगी। पोर्टल पर विभाग की ओर से वाहन का मॉडल, बैटरी का प्रकार व बैटरी क्षमता का सत्यापन कर वाहन क्रेताओं को पुनर्भरण और अनुदान राशि के क्लेम के लिए आवेदन के लिए वाहन पोर्टल पर अनुमति दी जाएगी।

Newspaper of 13 February, 2025

■ पशुपालन, गोपालन और डेयरी मंत्री राज. सरकार ने तरल नत्रजन भंडारण के लिए 13 जिलों में साइलो का लोकार्पण किया–

पशुपालन, गोपालन और डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के सभागार में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 13 जिलों में तरल नत्रजन भंडारण के लिए 3,000 लीटर के साइलो का वर्चुअल लोकार्पण किया।

- ♦ तरल नत्रजन पशु नस्ल सुधार के लिए किए जाने वाले कृत्रिम गर्भाधान में काम आता है।
- ♦ तरल नत्रजन की भण्डारण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए राज्य के 16 जिलों में 3-3 हजार लीटर क्षमता के वर्टिकल साइलो पूर्व में स्थापित हो चुके हैं।
- ♦ इस तरह अब राज्य के 29 जिलों में वर्टिकल साइलो की स्थापना हो जाने से तरल नत्रजन भंडारण की कुल क्षमता 93 हजार लीटर हो गई है।
- ♦ जयपुर और उदयपुर के साइलो की क्षमता 6-6 हजार लीटर की है।
- ♦ जैसलमेर में कृत्रिम गर्भाधान कवरेज को बढ़ाने के उद्देश्य से मिशन उत्कर्ष जैसलमेर की शुरुआत भी की गई है।

Newspaper of 15 February, 2025

■ 14 फरवरी, 2025 को केन्द्र सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर वकील कोटे से मनीष शर्मा को राजस्थान हाइकोर्ट का जज नियुक्त किया है। इस नोटिफिकेशन से पहले राष्ट्रपति भवन से मनीष शर्मा के नियुक्ति वारंट जारी हुए थे।

Newspaper of 16 February, 2025

■ अलवर, मिनी सचिवालय में 'वात्सल्य केन्द्र' खुला–

जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर महिलाओं एवं बच्चों के लिए मिनी सचिवालय के प्रथम तल पर तैयार कराए गए 'वात्सल्य केन्द्र' का फीता काटकर शुभारम्भ किया।

- ♦ जिला कलक्टर ने बताया कि मिनी सचिवालय में जिले के प्रमुख कार्यालय स्थित हैं।
- ♦ यहाँ बड़ी संख्या में महिलाकर्मी पदस्थापित तो हैं ही साथ ही जिलेभर से बड़ी संख्या में प्रतिदिन महिला परिवादी यहाँ आती हैं।
- ♦ इन महिलाओं व उनके बच्चों के लिए सुरक्षित चाइल्ड फ्रेंडली कक्ष वात्सल्य केन्द्र के रूप में तैयार कराया गया है, जिसमें महिलाकर्मी व महिला परिवादी अपने बच्चों को इस कक्ष में छोड़ सकती हैं।
- ♦ यहाँ चाइल्ड फ्रेंडली आकर्षक पेंटिंग की गई है, साथ ही बच्चों के लिए खिलौने, बैठने के लिए चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर, अच्छी क्वालिटी के मैट के साथ पेयजल की व्यवस्था की गई है।
- ♦ यहाँ पर दो महिला होमगार्ड बच्चों के केयर टेकर के रूप में तैनात रहेंगी। इनके द्वारा बच्चों को खेल-खेल में सिखाया भी जाएगा।
- ♦ वात्सल्य केन्द्र के अंदर ही तैयार कराए गए एक कक्ष में महिलाकर्मियों व आने वाले परिवादियों को सम्मान व प्राइवेसी के साथ बैठकर अपने बच्चों को स्तनपान कराने की सुविधा की गई है।

■ पुष्कर में बायोलॉजिकल पार्क मंजूर–बंगाल टाइगर, लायन सहित 12 वन्यजीव रखे जाएंगे

हाल ही में पुष्कर बायोलॉजिकल पार्क को मंजूरी मिली है। यहाँ सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 12 एनक्लोजर को मंजूरी दी है। यहाँ बंगाल टाइगर, लॉयन, पैंथर, डेजर्ट फॉक्स, इंडियन वुल्फ आदि रखे जाएंगे।

गौरतलब है कि इस बायोलॉजिकल पार्क को मंजूरी 3 वर्ष पहले ही मिल गई थी लेकिन जनता के लिए इसे अब खोला जाएगा। यहाँ हिरण की 4 प्रजातियाँ चिंकारा, ब्लैक बक, चीतल और सांभर भी रखे जाएंगे।

Newspaper of 19 February, 2025

■ राजस्थान के दस शहरों में 'नक्शा प्रोजेक्ट' की शुरुआत; संपत्तियों का होगा सटीक सीमांकन–

राजस्थान में अब शहरों की संपत्तियों का सटीक सीमांकन हो सकेगा। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

के तहत राज्य में भी 18 फरवरी, 2025 को 'नक्शा प्रोजेक्ट' की शुरुआत कर दी गई। इसके तहत नगरपालिकाओं की भूमिका ड्रोन सर्वे और डिजिटल मैपिंग होगी। इसके बाद घर बैठे जमीन सम्पत्ति से जुड़ी जानकारी देखी जा सकेगी। प्रोजेक्ट में अभी राजस्थान के दस शहरों को शामिल किया गया है। इनमें भिवाड़ी, किशनगढ़, ब्यावर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, पुष्कर, बगरू, बहरोड़, नवलगढ़ और नाथद्वारा शामिल हैं। स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने विभाग परिसर में इसकी शुरुआत की। इससे सम्पत्ति के स्वामित्व की जानकारी भी रजिस्टर होगी और लैंड रिकॉर्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगे।

Newspaper of 23 February, 2025

■ **पाली के सुमेरपुर में राज्य की पहली फिल्मसिटी बनेगी; 162 एकड़ में ₹ 500 करोड़ से तैयार होगी–**

राजस्थान की पहली फिल्म सिटी सुमेरपुर के निकट जवाई बाँध क्षेत्र में बनने जा रही है। 500 करोड़ की लागत से 152 एकड़ में फिल्मों की शूटिंग के लिए सैटअप तैयार किया जाएगा। राज्य सरकार ने फिल्म सिटी के लिए जमीन का आवंटन और कब्जा दे दिया है।

हैदराबाद की रामोजी तथा मुंबई के बाद यह देश की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म सिटी होगी। राजस्थान में फिल्म सिटी के निर्माण के बाद फिल्म और वृत्तचित्र निर्माण के लिए मुंबई या अन्य शहरों की तरफ स्थानीय निर्माताओं को भी जाना नहीं पड़ेगा।

सुमेरपुर के निकट कोलीवाड़ा रोड़ पर फिल्म सिटी को आकार दिया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को तीन साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद यहाँ फिल्मों का निर्माण शुरू हो जाएगा। फिल्म सिटी में शहर और गाँव की लोकेशन बनाई जाएगी। जिसमें स्टूडियो, अकेडमी, स्पोर्ट्स सेंटर इत्यादि होंगे। एक जंगल तैयार किया जाएगा, जिसमें नेचुरल लैंड स्कैपिंग जैसे कई मनमोहक नजारे होंगे।

सुमेरपुर लोकेशन चुनने के कारण–

- मारवाड़ और मेवाड़ यानी जोधपुर और उदयपुर का मिड वे है।
- जवाई बांध समेत आसपास का पूरा क्षेत्र प्राकृतिक है। घना जंगल और वन्यजीव बहुतायत है।
- कुंभलगढ़, रणकपुर, घाणेराव और नारलाई जैसे ऐतिहासिक और पर्यटल स्थल निकट हैं।
- सड़क और रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। फिल्म सिटी से कनेक्टिविटी बेहतर होगी।
- आउटडोर शूटिंग के लिए आसपास कई महत्त्वपूर्ण लोकेशन हैं।
- डेढ़ सौ किलोमीटर दूरी पर जोधपुर-उदयपुर के एयरपोर्ट हैं।
- जवाई बांध से बहुतायत में ट्रेनें चलती हैं। सुमेरपुर से अहमदाबाद-मुंबई-जयपुर हाईवे निकलता है।

फिल्मसिटी से निम्न फायदा होगा–

- राजस्थानी संस्कृति और पर्यटन को दुनिया में पहचान मिलेगी।
- स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सकेगा।
- फिल्म सितारों के आगमन से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
- राजस्थान के शौर्य और पराक्रम से जुड़ी गाथाओं पर भी फिल्मों का निर्माण हो सकेगा।

Newspaper of 25 February, 2025

■ **राजस्थान सरकार द्वारा 'ट्यूरिस्ट मोबाइल ऐप' बनाया जा रहा है, देशी-विदेशी पर्यटकों को पर्यटन स्थलों की जानकारी टिकट बुकिंग और पुलिस सुरक्षा मिलेगी–**

राजस्थान के पर्यटन स्थलों को देखने आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों को जल्द ही नया अनुभव मिलेगा। यहाँ आने पर वे स्मारक या पर्यटन स्थल की राह नहीं भटकेंगे, साथ ही आपात स्थिति में एक बटन दबाते ही उनके पास पुलिस मदद पहुँच जाएंगी। राजस्थान पर्यटन विभाग ऐसा ही एक टूरिस्ट मोबाइल ऐप तैयार कर रहा है। ऐप में राजस्थान के सभी पर्यटन स्थलों, सांस्कृतिक गतिविधियों और सुविधाओं की पूरी जानकारी मिलेगी क्योंकि पर्यटन को जब तक टेक्नोलॉजी से नहीं जोड़ा जाएगा, तक तक उसे नहीं बढ़ाया जा सकता।

Newspaper of 28 February, 2025

■ **उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बजट घोषणा 2025-26 के सामान्य वाद-विवाद/बहस के दौरान घोषणाएँ की–**

27 फरवरी, 2025 को उपमुख्यमंत्री और वित्तमंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में 2025-26 के बजट पर बहस के दौरान घोषणाएँ कर जन सुविधाओं को प्राथमिकता दी। पानी के लिए 330 करोड़ और 1870 करोड़ की 127 सड़कों की घोषणाएँ की। दिया कुमारी ने कहा कि राज्य को केन्द्रीय करों में हिस्से के रूप में वर्ष 2023-24 के विरुद्ध वर्ष 2025-26 में 17 हजार 653 करोड़ रुपए अधिक प्राप्त हुए। इससे राज्य को कुल 85 हजार 716 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। एसेट मॉनेटाइजेशन यथा लैंड पूलिंग, लैंड एग्रेगेशन, आईएनवीआइटी के माध्यम से 4 हजार 750 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा।

प्रमुख घोषणाएँ

पेजयल–330 करोड़ रुपए की लागत से पाली, भीलवाड़ा, दौसा, ब्यावर, टोंक, जयपुर, सीकर में पेयजल कार्य। इंदिरा

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

गांधी नहर से जसवंत सागर बांध मे पानी का पुनर्भकरण कर जोधपुर के बिलाड़ा को पेयजल आपूर्ति के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनेगी।

ऊर्जा–33 केवी के दस, 132 केवी के पाँच और 220 केवी के चार ग्रिड सब-स्टेशन बनेंगे।

सड़क–1870 करोड़ खर्च कर 127 सड़क-फ्लाईओवर। अजमेर के चारों ओर 3 करोड़ की लागत की रिंग रोड़ के लिए डीपीआर बनेगी।

विकास व नागरिक सुविधा–आपदा प्रबंधन को हाईटेक बनाने के लिए 55 नए क्विक रिस्पॉन्स वाहनों पर 120 करोड़ खर्च होंगे। वहीं बीकानेर, भरतपुर, बाड़मेर, सीकर व बाँसवाड़ा में ऊँची इमारतों में आसानी से आग बुझाने के लिए हाइड्रोलिक लैडर प्लेटफॉर्म खरीदे जाएंगे। बाकी नगरीय निकायों में 3000 से 4500 लीटर क्षमता के फायर वाटर टेंडर्स उपलब्ध होंगे।

शहरी विकास–चूरू, नगर, डीग, सीकरी, भरतपुर, केकड़ी, लूणकरणसर, जयपुर, निवाई, अंता, मसूदा, बूंदी, पोकरण में सीवरेज-ड्रेनेज, पार्क बस स्टैंड सहित अन्य विकास कार्य। जयपुर के विद्याधर नगर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और जयपुर में अजमेर रोड पर कमला नेहरू नगर से भांकरोटा पुलिया तक बारिश के पानी की निकासी के लिए पक्के नाले का निर्माण होगा।

अन्य घोषणाएँ–

- वाद्य यंत्र, पाक कला, आस्था केन्द्रों, ऐतिहासिक महत्त्व के स्थल, चित्रकारी, भित्ती चित्र, नृत्य और गायन के प्रलेखन कार्य के लिए सौंध माटी आदि धरोहर प्रलेखन योजना शुरू होगी।
- पाँच हजार आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों की मरम्मत।
- 3236 बांध जलसंसाधन विभाग को हस्तांरित होंगे।
- कोटा में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय खोला जाएगा।
- स्टेट डाटा सेंटर में हाई परफॉर्मेंस कम्प्यूटिंग सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर पर 65 करोड़ रुपए।
- जोधपुर में एसटीपी का निर्माण।
- भीलवाड़ा के शाहपुरा में औद्योगिक पार्क और लालसोट में वुडलैंड पार्क।
- रोग नियंत्रण के लिए पशुपालकों को टीके उपलब्ध कराने के लिए कोल्ड चैन युक्त वाहन और रेफ्रिजरेटर।
- जयपुर जिले के भांकरोटा और जोधपुर जिले के केरू में ट्रोमा सेंटर।
- माँ योजना के तहत के राजकीय चिकित्सा संस्थाओं में उच्च तकनीक के प्रोसिजर में रोबोटिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी प्रोसिजर, प्लास्टिक सर्जरी एंड स्क्रीन ट्रांसप्लांट, कॉर्डियक एंड वैस्कुलर सर्जरी।

□□□

संजीव प्रकाशन

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

संजीव®

50 वर्षों से आपका विश्वसनीय

आपकी सफलता में सदैव आपका सहयोगी

कैलाश नागौरी की शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु संजीव प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हिन्दी की प्रसिद्ध पुस्तकें बाजार में उपलब्ध

संजीव प्रकाशन की अन्य उपयोगी पुस्तकें

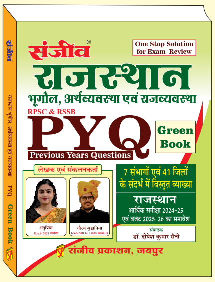

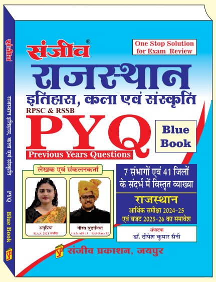

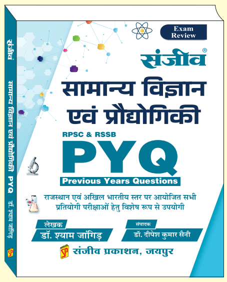

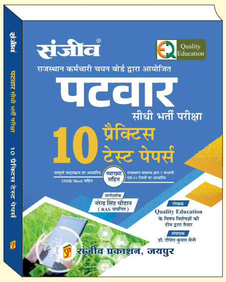

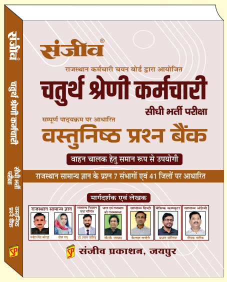

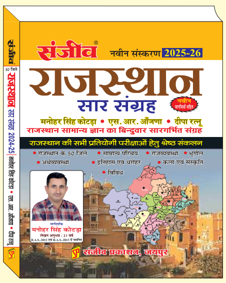

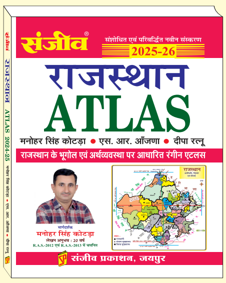

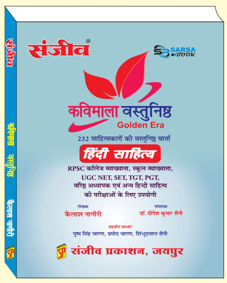

संजीव प्रकाशन

Join Our Telegram

संजीव Telegram चैनल एवं Website से परीक्षा उपयोगी पाठ्य सामग्री नि:शुल्क प्राप्त करें। साथ ही संजीव वेबसाइट से आप Books एवं E-Books भी खरीद सकते हैं।

प्रकाशक–संजीव प्रकाशन, जयपुर
Visit us at : www.sanjivprakashan.com